



नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध: जब डिजिटल पाबंदियों ने गिरा दी सरकार

नेपाल की प्रेषण-निर्भर अर्थव्यवस्था में 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो एक ऐसे आंदोलन में बदल गए कि सरकार ही गिर गई। जो शुरुआत में डिजिटल पाबंदी थी, वही एक ऐसे व्यापक असंतोष का कारण बन गई, जहाँ सोशल मीडिया आर्थिक जीवनरेखा की तरह काम करता है।

आर्थिक हताशा का परफ़ेक्ट तूफ़ान

आर्थिक पतन

घरेलू अर्थव्यवस्था दशकों से कम उत्पादकता और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण वास्तविक विकास हासिल करने में जूझ रही है।

भ्रष्टाचार पर गुस्सा

राजनेता संपन्न होते गए, जबकि आम नागरिकों को बेरोज़गारी और सीमित अवसरों का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया का पर्दाफ़ाश

राजनेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी ऐशो-आराम भरी जीवनशैली की तस्वीरें साझा कर रहे थे, जिससे जनता में रोष और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध साझा करने की लहर उठी।

प्रतिबंध को आलोचना को दबाने और भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश माना गया, जिसने सुलगते असंतोष को भड़कते प्रतिरोध में बदल दिया।

नेपाल की प्रेषण पर निर्भरता

—

विदेशों में आबादी

नेपाल की 8% से अधिक जनसंख्या विदेशों में काम करती है, मुख्यतः खाड़ी देशों, मलेशिया और भारत में।

33%

प्रेषण से जीडीपी

प्रेषण-से-जीडीपी अनुपात में नेपाल दुनिया में चौथे स्थान पर है — टोंगा, ताजिकिस्तान और लेबनान के बाद।



फ़ेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया सेवाएँ प्रवासी मज़दूरों और उनके परिवारों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए जीवनरेखा का काम करती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्रतिबंध नेपाल की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ।

UPSC AFTER 10TH BATCH

LIVE ONLINE CLASSES
Course Duration 4Year

Discover the Best Time to Study
and Boost Your Productivity!

LIMITED
OFFER



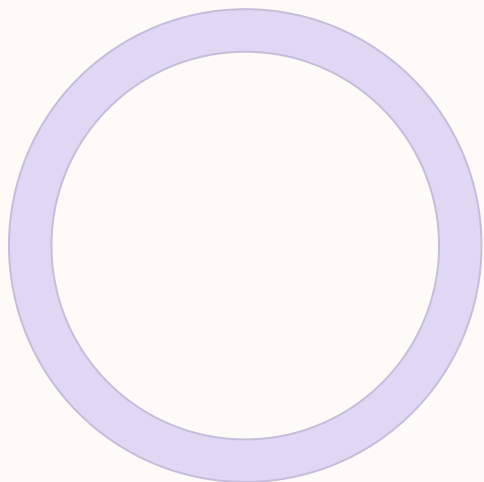
-  Bilingual
-  4 Year Validity
-  View on App
-  Unlimited Views
-  PDF Notes



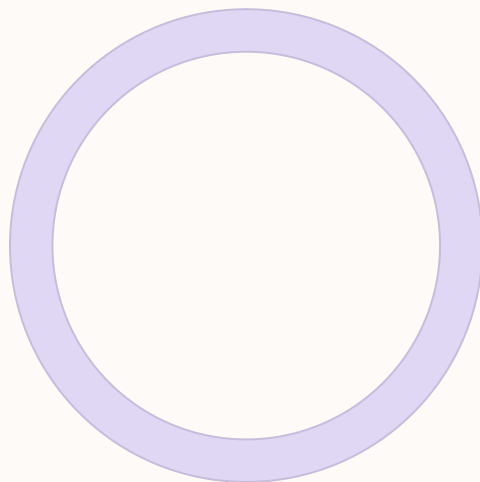
8285894079

Call: 8750711100/22/33/44/55

युवा उभार की चुनौती



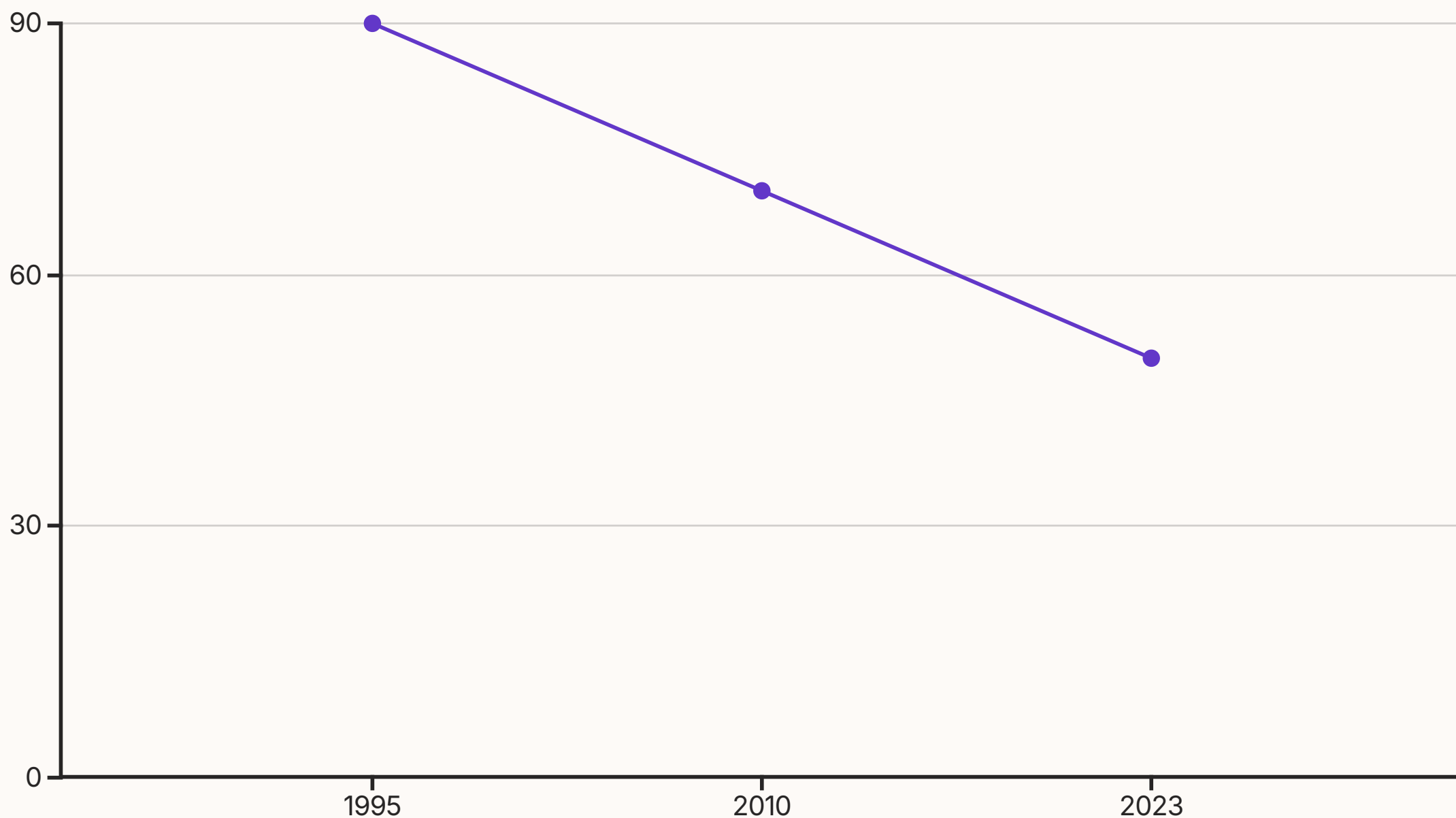
नेपाल की 3 करोड़ से अधिक आबादी में से 20% से अधिक युवा इसी आयु वर्ग में आते हैं।



कार्यशील आयु वर्ग कुल जनसंख्या का 40% से अधिक है।

यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन नेपाल में "युवा उभार" (Youth Bulge) की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन सीमित घरेलू अवसरों के कारण लगातार प्रवास बढ़ रहा है, जिससे एक ओर प्रेषण के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल रहा है, तो दूसरी ओर उभरते क्षेत्रों में ब्रेन ड्रेन की गंभीर चुनौती खड़ी हो रही है।

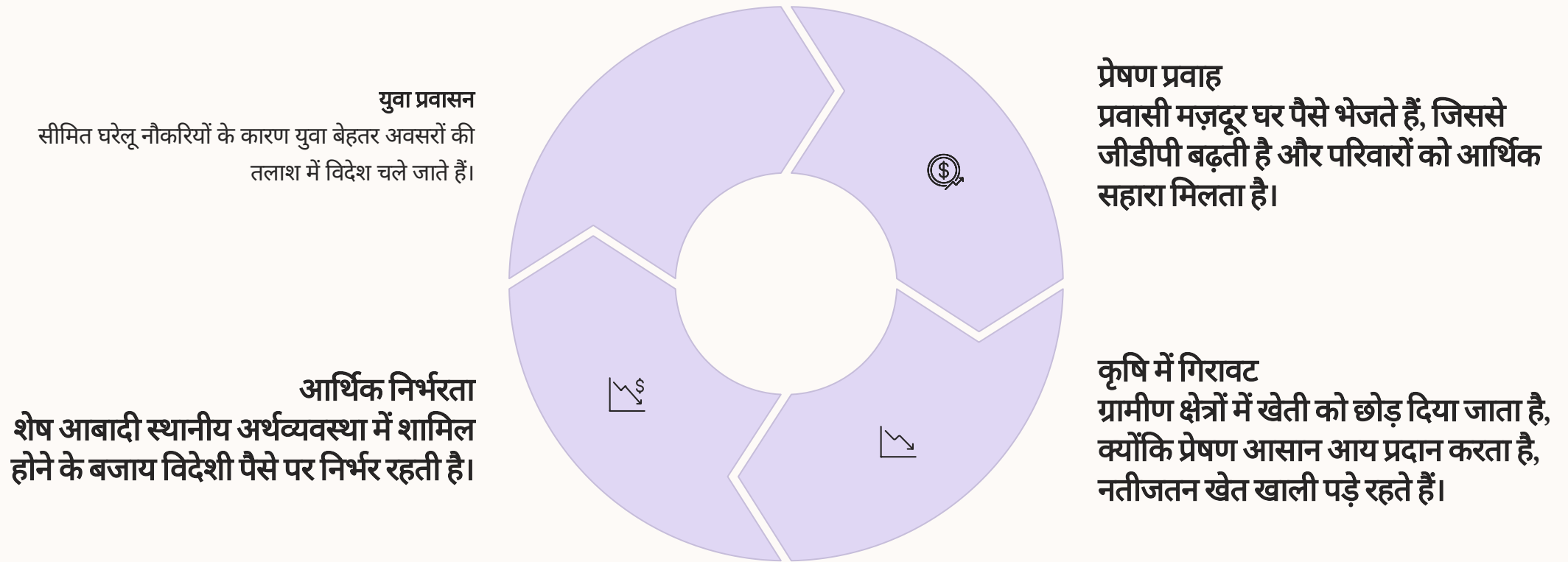
गरीबी घटने के बावजूद आर्थिक ठहराव



हालाँकि गरीबी दर 90% से घटकर 50% से नीचे आ गई, फिर भी नेपाल की 4.2% औसत वार्षिक विकास दर दक्षिण एशिया के आठ देशों में छठे स्थान पर रही।

अर्थव्यवस्था कम उत्पादकता, कमजोर बुनियादी ढाँचे और सीमित निर्यात से जूझती रही। गरीबी में कमी का मुख्य कारण घरेलू आर्थिक विकास नहीं, बल्कि प्रेषण (Remittances) ही रहा।

प्रेषण पर निर्भरता का चक्र



यह चक्रीय निर्भरता नेपाल की जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) से वास्तविक लाभ उठाने की क्षमता को कमजोर करती है और दीर्घकालिक संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी करती है।

JOIN NOW!!!



EDITION 2025



GOVERNMENT OF INDIA **PRESS INFORMATION BUREAU** *TEST SERIES WITH RFR*



PRESENTED BY OJAANK SIR



8285894079

संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियाँ

विनिर्माण में गिरावट

पहले से ही कम आधार से लगातार गिरावट, लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्रों में कमजोर प्रतिस्पर्धा ने विकास की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।

पर्यटन का अल्पविकास

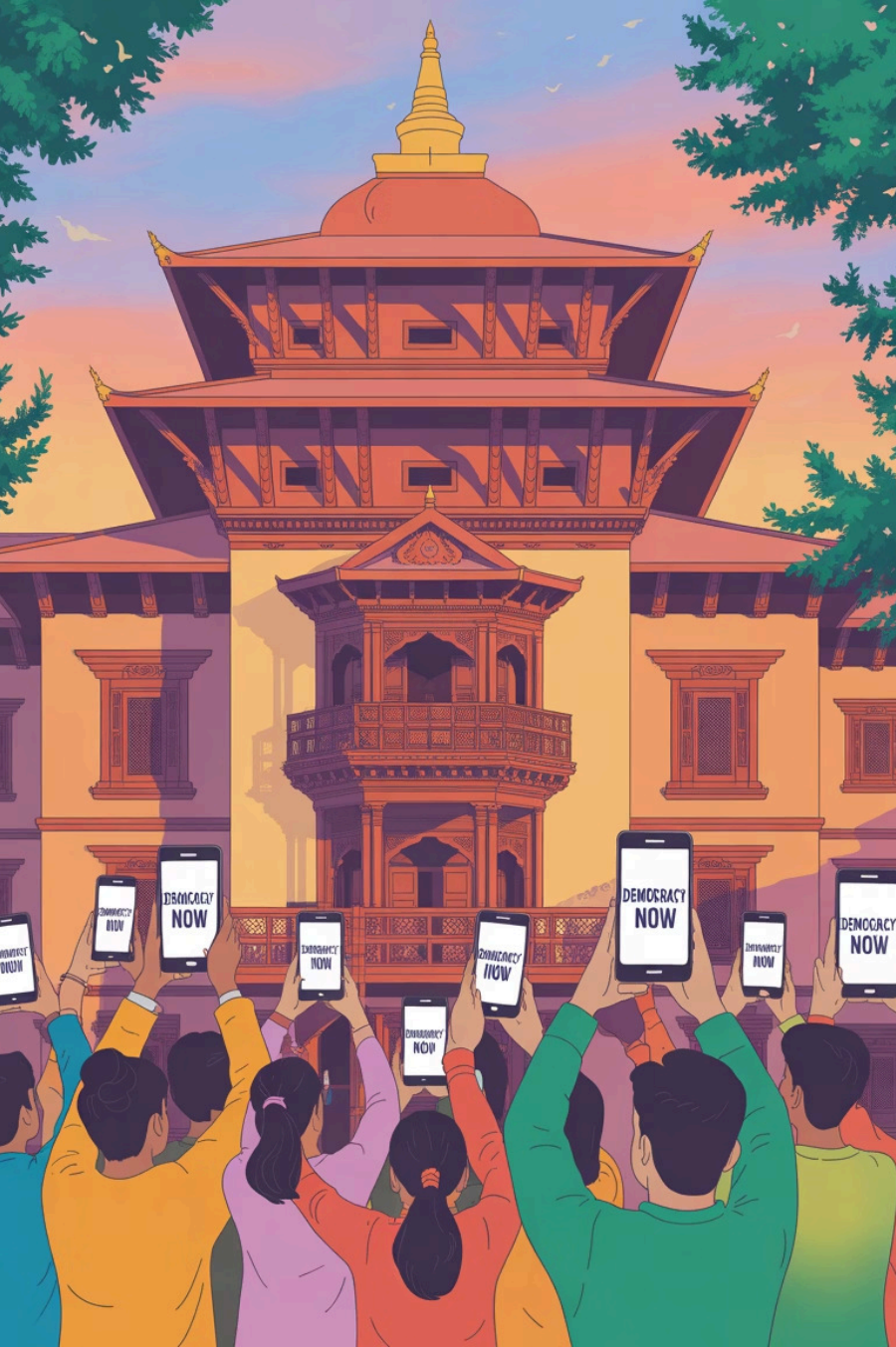
नेपाल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षणों के बावजूद यह प्रमुख विकास और रोज़गार वाला क्षेत्र अब भी अल्पविकसित है।

जलविद्युत परियोजनाओं में देरी

धीमी प्रगति ने अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने और मज़बूत व सतत विकास को गति देने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

निर्यात बाधाएँ

उच्च टैरिफ, उत्पाद शुल्क और बढ़ती विनिमय दर ने निर्यात प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विविधीकरण को और सीमित कर दिया है।



जब डिजिटल जीवनरेखाएँ राजनीतिक विवाद बन जाती हैं

"जैसे-जैसे रोज़गार के लिए विदेश जाने वाले मज़दूरों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में प्रेषण का प्रवाह नेपाल में विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।"

सोशल मीडिया प्रतिबंध ने नेपाल की प्रेषण-निर्भर अर्थव्यवस्था को ज़रूरत के ठीक उलट संकेत दिया। जिस देश में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रवासी मज़दूरों और उनके परिवारों को महाद्वीपों के पार जोड़ने वाली *आर्थिक जीवनरेखा* हैं, वहाँ इन चैनलों पर रोक व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल की चिंगारी बन गई।

नेपाल का संकट यह दर्शाता है कि प्रेषण-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में डिजिटल कनेक्टिविटी अब *आर्थिक अस्तित्व* से अलग नहीं की जा सकती। ऐसे में सोशल मीडिया प्रतिबंध सिर्फ राजनीतिक सेंसरशिप नहीं, बल्कि नागरिकों की आजीविका के खिलाफ आर्थिक युद्ध है।

Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें



IAS with Ojaankk Sir



Ojaankk_Sir



IAS with Ojaankk Sir



8285894079



8285894079



www.ojaank.com/